EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

27 JUNE - 4 JULY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM
Genius

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques: Under RBI's proposed framework, which entities will be allowed to participate in the term money market as both borrowers and lenders?
प्रश्न: RBI के प्रस्तावित ढांचे के तहत किन संस्थाओं को टर्म मनी मार्केट में उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी?

A) Only Commercial Banks / केवल वाणिज्यिक बैंक

B) NBFCs, HFCs and Financial Institutions / NBFCs, HFCs एवं वित्तीय संस्थान

C) Only Corporate Companies / केवल कॉर्पोरेट कंपनियां

D) Mutual Funds and Insurance Companies / म्यूचुअल फंड एवं बीमा कंपनियां

E) Foreign Banks Only / केवल विदेशी बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has proposed expanding the term money market to include Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and other financial institutions.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने टर्म मनी मार्केट का दायरा बढ़ाकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

• Under the proposed framework, all Indian Financial Institutions, NBFCs and Housing Finance Companies (HFCs) will be allowed to participate as both borrowers and lenders.

• प्रस्तावित ढांचे के तहत सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों, NBFCs तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) को उधारकर्ता एवं ऋणदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

• Companies will be permitted to participate only as lenders in the term money market.

• कंपनियों को टर्म मनी मार्केट में केवल ऋणदाता (Lender) के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।

• At present, only banks and standalone primary dealers are allowed to participate in the term money market.

• वर्तमान में केवल बैंक एवं स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को ही टर्म मनी मार्केट में भाग

लेने की अनुमति है।

- The RBI has invited stakeholder comments and feedback on the proposal until 17 July 2026.
- RBI ने इस प्रस्ताव पर हितधारकों से 17 जुलाई 2026 तक सुझाव एवं टिप्पणियाँ मांगी हैं।
- The move aims to improve liquidity conditions and provide an alternative source of short-term funding to market participants.
- इस कदम का उद्देश्य तरलता (Liquidity) में सुधार करना तथा बाजार सहभागियों को अल्पकालिक वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है।
- RBI stated that a more active term money market would strengthen monetary policy transmission by linking overnight interest rates with longer-term interest rates.
- RBI के अनुसार अधिक सक्रिय टर्म मनी मार्केट, ओवरनाइट ब्याज दरों और दीर्घकालिक ब्याज दरों के बीच बेहतर संबंध स्थापित कर मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) को मजबूत करेगा।

About Term Money Market | टर्म मनी मार्केट के बारे में

- The Term Money Market is a segment of the money market where funds are borrowed and lent for periods exceeding 14 days and up to one year.
- टर्म मनी मार्केट मनी मार्केट का वह खंड है जिसमें 14 दिनों से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए धन उधार लिया और दिया जाता है।
- It helps financial institutions manage short-term liquidity requirements.
- यह वित्तीय संस्थानों को अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता करता है।

Static GK

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI का मुख्यालय – मुंबई
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: According to NPCI BHIM Services Limited (NBSL), BHIM is set to evolve into which type of platform?

प्रश्न: NPCI BHIM Services Limited (NBSL) के अनुसार, BHIM किस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित होने जा रहा है?

A) Digital Financial Services Platform / डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफ़ॉर्म

B) Digital Banking Platform / डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म

C) E-commerce Platform / ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म

D) Digital Investment Exchange / डिजिटल निवेश एक्सचेंज

E) Cryptocurrency Payment Platform / क्रिप्टोकरेंसी भुगतान प्लेटफ़ॉर्म

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- BHIM (Bharat Interface for Money), developed by NPCI BHIM Services Limited (NBSL), is set to evolve from a UPI payment app into a Digital Financial Services Platform.
- NPCI BHIM Services Limited (NBSL) द्वारा विकसित BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) अब केवल UPI भुगतान ऐप न रहकर डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित होने जा रहा है।
- According to Lalitha Nataraj, Managing Director & CEO of NBSL, BHIM will soon offer products such as credit cards, loans, pension schemes, insurance, and investments in partnership with banks and NBFCs.
- NBSL की प्रबंध निदेशक एवं CEO ललिता नटराज के अनुसार, BHIM जल्द ही बैंकों एवं NBFCs के सहयोग से क्रेडिट कार्ड, ऋण, पेंशन योजनाएँ, बीमा तथा निवेश जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- In May 2026, BHIM recorded 244 million monthly transactions.

- मई 2026 में BHIM पर 244 मिलियन मासिक लेनदेन दर्ज किए गए।
- The total transaction value on BHIM during May 2026 was ₹26,952 crore.
- मई 2026 में BHIM के माध्यम से कुल ₹26,952 करोड़ मूल्य के लेनदेन हुए।
- BHIM was developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) and was launched on 30 December 2016.
- BHIM का विकास नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया गया था और इसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- BHIM stands for Bharat Interface for Money.
- BHIM का पूर्ण रूप Bharat Interface for Money (भारत इंटरफेस फॉर मनी) है।
- BHIM Launch Date – 30 December 2016
- BHIM का शुभारंभ – 30 दिसंबर 2016
- National Payments Corporation of India (NPCI) Established – 2008
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्थापना – 2008
- NPCI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- NPCI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- UPI (Unified Payments Interface) is an instant real-time payment system developed by NPCI.
- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) NPCI द्वारा विकसित एक त्वरित रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है।

Ques: RBI’s holdings of Government Securities (G-Secs) rose to the highest level in how many years as of March 2026?
प्रश्न: मार्च 2026 तक RBI की सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में हिस्सेदारी कितने वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई?

A) 5 Years / 5 वर्ष

B) 8 Years / 8 वर्ष

C) 10 Years / 10 वर्ष

D) 13 Years / 13 वर्ष

E) 15 Years / 15 वर्ष

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) increased its holdings of Government Securities (G-Secs) after conducting large-scale bond purchases, taking its share to a multi-year high.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद के बाद सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में अपनी हिस्सेदारी को कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।

• RBI's share in outstanding Government Securities increased from 14.5% at the end of December 2025 to 17.6% by the end of March 2026.

• दिसंबर 2025 के अंत में बकाया सरकारी प्रतिभूतियों में RBI की हिस्सेदारी 14.5% थी, जो मार्च 2026 के अंत तक बढ़कर 17.6% हो गई।

• This is the highest level of RBI's ownership of Government Securities in the last 13 years.

• यह पिछले 13 वर्षों में RBI की सरकारी प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी का उच्चतम स्तर है।

• RBI carried out large-scale Open Market Operations (OMOs) to inject durable liquidity into the banking system.

• RBI ने बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक तरलता (Liquidity) बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) किए।

• During the March quarter, RBI purchased Government Securities worth about ₹3.5 lakh crore through OMOs and around ₹90,000 crore through secondary market operations.

• मार्च तिमाही के दौरान RBI ने OMO के माध्यम से लगभग ₹3.5 लाख करोड़ तथा द्वितीयक बाजार के माध्यम से लगभग ₹90,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे।

• In FY26, RBI purchased a record ₹8.56 lakh crore worth of Government Securities, accounting for more than 80% of the government's net borrowing.

• FY26 में RBI ने रिकॉर्ड ₹8.56 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे, जो सरकार की शुद्ध उधारी के 80% से अधिक के बराबर है।

• Falling crude oil prices and expected foreign capital inflows are likely to improve liquidity conditions, reducing the need for further large-scale bond purchases.

- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और संभावित विदेशी पूंजी प्रवाह से तरलता की स्थिति बेहतर होने तथा आगे बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद की आवश्यकता कम होने की संभावना है।

Static GK

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI का मुख्यालय – मुंबई
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: As per the RBI's final directions on the Trade Receivables Discounting System (TReDS), what is the minimum net worth required for entities providing discounting services?

प्रश्न: RBI द्वारा Trade Receivables Discounting System (TReDS) पर जारी अंतिम दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिस्काउंटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कितनी निर्धारित की गई है?

A) ₹10 crore / ₹10 करोड़

B) ₹15 crore / ₹15 करोड़

C) ₹20 crore / ₹20 करोड़

D) ₹25 crore / ₹25 करोड़

E) ₹50 crore / ₹50 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) issued its final directions on the Trade Receivables Discounting System (TReDS) to simplify the system and improve access to working capital for MSMEs.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने MSMEs के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुँच को सरल एवं सुगम बनाने हेतु Trade Receivables Discounting System (TReDS) पर अपने अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए।
- RBI has prescribed a minimum net worth of ₹25 crore for entities providing discounting services under TReDS.
- RBI ने TReDS के तहत डिस्काउंटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए ₹25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ निर्धारित की है।
- The minimum net worth must be certified by a statutory auditor.
- निर्धारित न्यूनतम नेटवर्थ का वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा।
- Existing entities providing TReDS services have been given time until 31 March 2028 to comply with the prescribed net worth criterion.
- वर्तमान में TReDS सेवाएँ प्रदान कर रही संस्थाओं को 31 मार्च 2028 तक इस नेटवर्थ मानदंड का पालन करने की समय-सीमा दी गई है।
- Trade Receivables Discounting System (TReDS) is an online platform that enables MSMEs to auction their invoices or trade receivables to banks and financial institutions for faster realization of working capital.
- Trade Receivables Discounting System (TReDS) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो MSMEs को अपनी चालानों (Invoices) अथवा व्यापारिक देय राशियों (Trade Receivables) की नीलामी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कर कार्यशील पूंजी शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Trade Receivables Discounting System (TReDS) was introduced by RBI in 2014.
- Trade Receivables Discounting System (TReDS) की शुरुआत RBI द्वारा 2014 में की गई थी।
- TReDS is an electronic platform for financing the trade receivables of Micro,

Small and Medium Enterprises (MSMEs).

- TReDS सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यापारिक देय राशियों के वित्तपोषण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है।
- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1935
- RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- RBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises.
- MSME का पूर्ण रूप Micro, Small and Medium Enterprises (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) है।

Ques: Which city is likely to host the 57th meeting of the GST Council in July 2026?

प्रश्न: जुलाई 2026 में GST परिषद की 57वीं बैठक किस शहर में आयोजित होने की संभावना है?

A) Mumbai / मुंबई

B) New Delhi / नई दिल्ली

C) Bengaluru / बेंगलुरु

D) Kolkata / कोलकाता

E) Hyderabad / हैदराबाद

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Kolkata is likely to host the 57th meeting of the GST Council in the second half of July 2026.
- जुलाई 2026 के दूसरे पखवाड़े में GST परिषद की 57वीं बैठक कोलकाता में आयोजित होने की संभावना है।

- The meeting is expected to discuss the next phase of GST reforms following the rollout of GST 2.0.
- इस बैठक में GST 2.0 के बाद अगले चरण के GST सुधारों पर चर्चा होने की संभावना है।
- The previous GST Council meeting was held on 3 September 2025 after a gap of nearly nine months.
- पिछली GST परिषद बैठक 3 सितंबर 2025 को लगभग नौ महीने के अंतराल के बाद आयोजित हुई थी।
- GST 2.0 introduced rate rationalisation and several measures aimed at easing tax compliance.
- GST 2.0 के तहत कर दरों के युक्तिकरण (Rate Rationalisation) तथा अनुपालन को सरल बनाने के कई उपाय लागू किए गए थे।
- Experts expect the Council to address issues related to Input Tax Credit (ITC) under the inverted duty structure.
- विशेषज्ञों का मानना है कि परिषद उल्टे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) के अंतर्गत Input Tax Credit (ITC) से संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकती है।
- Discussions may also focus on reducing tax cascading, improving competitiveness and strengthening India's manufacturing sector.
- चर्चा का केंद्र करों के दोहराव को कम करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर भी हो सकता है।
- A proposal has been made to reduce GST on autism care centres and allied services from 18% to 5%.
- ऑटिज्म देखभाल केंद्रों एवं संबंधित सेवाओं पर GST को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
- The meeting would be one of the first major constitutional body meetings in West Bengal after the Assembly elections.
- यह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में किसी प्रमुख संवैधानिक निकाय की पहली बड़ी बैठकों में से एक होगी।

Static GK

- GST was launched in India on – 1 July 2017
- भारत में GST लागू हुआ – 1 जुलाई 2017
- GST stands for – Goods and Services Tax
- GST का पूर्ण रूप – वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)
- GST Council is constituted under – Article 279A of the Constitution

- GST परिषद का गठन – संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है।
- Chairperson of GST Council – Union Finance Minister
- GST परिषद के अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री
- Union Finance Minister – Nirmala Sitharaman
- केंद्रीय वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण
- Headquarters of GST Council Secretariat – New Delhi
- GST परिषद सचिवालय का मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: Under the RBI's new compensation framework for small-value digital banking frauds, what is the maximum compensation a customer can receive?
प्रश्न: RBI के छोटे मूल्य के डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए नए मुआवजा ढांचे के तहत ग्राहक को अधिकतम कितना मुआवजा मिल सकता है?

A) ₹10,000 / ₹10,000
B) ₹20,000 / ₹20,000
C) ₹25,000 / ₹25,000
D) ₹50,000 / ₹50,000
E) ₹75,000 / ₹75,000

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has finalized the compensation framework for victims of small-value digital banking frauds.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छोटे मूल्य की डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए मुआवजा ढांचा (Compensation Framework) को अंतिम रूप दिया है।
- The framework will come into effect from 1 January 2027.
- यह ढांचा 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।
- It introduces a structured compensation mechanism, defines the responsibilities of banks, and strengthens safeguards against cyber fraud.
- यह संरचित मुआवजा तंत्र लागू करता है, बैंकों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है

तथा साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

- Customers suffering losses of up to ₹50,000 are eligible for compensation, subject to specified conditions.
- ₹50,000 तक की हानि उठाने वाले ग्राहक, निर्धारित शर्तों के अधीन, मुआवजे के पात्र होंगे।
- The maximum compensation under the scheme is ₹25,000. Victims will receive 85% of the net loss or ₹25,000, whichever is lower.
- इस योजना के तहत अधिकतम मुआवजा ₹25,000 होगा। पीड़ित को शुद्ध हानि का 85% अथवा ₹25,000, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
- Customers must report the fraud to both the bank and the National Cyber Crime Reporting Portal or Cyber Crime Helpline 1930 within five calendar days of the incident.
- ग्राहकों को घटना के पाँच कैलेंडर दिनों के भीतर अपने बैंक तथा National Cyber Crime Reporting Portal या Cyber Crime Helpline 1930 पर शिकायत दर्ज करनी होगी।
- The compensation can be availed only once in a lifetime and is applicable only to electronic banking transactions occurring on or after 1 January 2027.
- यह मुआवजा जीवन में केवल एक बार प्राप्त किया जा सकेगा तथा 1 जनवरी 2027 या उसके बाद हुई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी पर ही लागू होगा।
- Complaint resolution timelines are 45 calendar days for domestic frauds and 60 calendar days for cross-border frauds.
- शिकायत निस्तारण की समय-सीमा घरेलू धोखाधड़ी के लिए 45 दिन तथा सीमा-पार (Cross-border) धोखाधड़ी के लिए 60 दिन निर्धारित की गई है।

The RBI has created the shared responsibility model:

- For Losses Below Amount ₹29,412 - RBI: 65%, Customer’s Bank: 10%, Beneficiary Bank: 10%
- For Losses Above ₹29,412 - RBI Contribution: ₹19,118, Customer’s Bank: ₹2,941, Beneficiary Bank: ₹2,941
- Cross-Border Fraud Cases - RBI Contribution: ₹19,118, Customer’s Bank Contribution: ₹5,882

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1935
- RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- RBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- National Cyber Crime Helpline Number – 1930
- राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर – 1930
- National Cyber Crime Reporting Portal is the Government of India's official platform for reporting cyber crimes.
- National Cyber Crime Reporting Portal भारत सरकार का साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु आधिकारिक पोर्टल है।
- The new RBI compensation framework will be effective from 1 January 2027.
- RBI का नया मुआवजा ढांचा 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।

Ques: The Asian Development Bank (ADB) approved a USD 42.2 million Small Expenditure Financing Facility (SEFF) to support the development of which sector in Northeast India?

प्रश्न: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पूर्वोत्तर भारत में किस क्षेत्र के विकास के लिए **42.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की **Small Expenditure Financing Facility (SEFF)** को मंज़ूरी दी है?

A) Tea Industry / चाय उद्योग

B) Bamboo Industry / बांस उद्योग

C) Handloom Industry / हथकरघा उद्योग

D) Rubber Industry / रबर उद्योग

E) Horticulture Sector / बागवानी क्षेत्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The **Asian Development Bank (ADB)** has approved a **USD 42.2 million Small Expenditure Financing Facility (SEFF)** to support the development of the **bamboo industry** in **Northeast India**.
- **एशियाई विकास बैंक** (ADB) ने **पूर्वोत्तर भारत** में **बांस उद्योग** के विकास के लिए **42.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की **Small Expenditure Financing Facility (SEFF)** को मंजूरी दी है।
- The project will be implemented in **six Northeastern States—Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura**.
- यह परियोजना **पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों—असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा**—में लागू की जाएगी।
- The initiative aims to strengthen the bamboo value chain, promote sustainable livelihoods and enhance economic opportunities in the region.
- इस पहल का उद्देश्य **बांस मूल्य श्रृंखला (Value Chain)** को मजबूत करना, **सतत आजीविका** को बढ़ावा देना तथा क्षेत्र में **आर्थिक अवसरों** का विस्तार करना है।
- **SEFF (Small Expenditure Financing Facility)** is a financing instrument of the **Asian Development Bank (ADB)**.
- **SEFF (Small Expenditure Financing Facility) एशियाई विकास बैंक (ADB)** का एक **वित्तपोषण साधन (Financing Instrument)** है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- **Asian Development Bank (ADB)** Established – **1966**
- **एशियाई विकास बैंक (ADB)** की स्थापना – **1966**
- **ADB Headquarters – Manila, Philippines**
- **ADB का मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस**
- **ADB Members** – **69** (49 from Asia and the Pacific, 20 from outside the region)
- **ADB के सदस्य** – **69** (49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से तथा 20 क्षेत्र के बाहर से)
- **Bamboo** is known as **"Green Gold"** due to its economic and environmental importance.
- **बांस** को उसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व के कारण **"हरित स्वर्ण (Green Gold)"** कहा जाता है।
- **North Eastern Region (NER)** comprises **8 States—Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura**.
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र** (NER) में **8 राज्य** शामिल हैं—**अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,**

मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

Ques: Who has decided not to seek reappointment as MD & CEO of Kotak Mahindra Bank after the completion of his current term?

प्रश्न: अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं लेने का निर्णय किसने लिया है?

A) Uday Kotak / उदय कोटक

B) Shanti Ekambaram / शांति एकाम्बरम

C) Ashok Vaswani / अशोक वासवानी

D) Dipak Gupta / दीपक गुप्ता

E) Nitin Chugh / नितिन चुघ

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Kotak Mahindra Bank MD & CEO Ashok Vaswani has decided not to seek reappointment after the completion of his three-year term.

• कोटक महिंद्रा बैंक के MD एवं CEO अशोक वासवानी ने अपने तीन वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं लेने का निर्णय लिया है।

• His current term is scheduled to end on 31 December 2026.

• उनका वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है।

• Vaswani cited personal reasons for stepping down from the position.

• वासवानी ने पद छोड़ने के लिए व्यक्तिगत कारणों (Personal Reasons) का हवाला दिया है।

• Kotak Mahindra Bank has initiated the process of appointing a new MD & CEO within the prescribed regulatory timeline.

• कोटक महिंद्रा बैंक ने निर्धारित नियामकीय समय-सीमा के भीतर नए MD एवं CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

• Ashok Vaswani took charge as MD & CEO on 1 January 2024, succeeding

founder Uday Kotak.

- अशोक वासवानी ने 1 जनवरी 2024 को संस्थापक उदय कोटक के उत्तराधिकारी के रूप में MD एवं CEO का पदभार संभाला था।
- During his tenure, the bank focused on inorganic growth strategies, retail expansion and technology upgrades.
- उनके कार्यकाल में बैंक ने अकार्बनिक विकास (Inorganic Growth), रिटेल विस्तार तथा तकनीकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया।
- Under his leadership, Kotak Mahindra Bank acquired Standard Chartered Bank India's personal loan portfolio.
- उनके नेतृत्व में कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया।
- He also oversaw the resolution of technology-related issues following RBI restrictions imposed in 2024.
- उन्होंने 2024 में RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद तकनीकी चुनौतियों के समाधान की निगरानी भी की।

Static GK

- Kotak Mahindra Bank Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Kotak Mahindra Bank Founded – 1985
- कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना – 1985
- Founder – Uday Kotak
- संस्थापक – उदय कोटक
- Ashok Vaswani assumed charge as MD & CEO on 1 January 2024.
- अशोक वासवानी ने 1 जनवरी 2024 को MD एवं CEO का पदभार ग्रहण किया था।

Ques: Paisabazaar, in partnership with SBM Bank (India) Limited, has launched which Fixed Deposit (FD)-backed secured credit card?

प्रश्न: Paisabazaar ने SBM Bank (India) Limited के साथ मिलकर कौन-सा Fixed Deposit (FD)-backed Secured Credit Card लॉन्च किया है?

A) SBM Paisabazaar Smart Credit Card / एसबीएम पैसाबाज़ार स्मार्ट क्रेडिट कार्ड

B) SBM Paisabazaar Paisa+ Credit Card / एसबीएम पैसाबाज़ार पैसा+ क्रेडिट कार्ड

C) SBM Paisabazaar Secure Card / एसबीएम पैसाबाज़ार सिक्योर कार्ड

D) Paisabazaar FD Credit Card / पैसाबाज़ार एफडी क्रेडिट कार्ड

E) SBM Digital Credit Card / एसबीएम डिजिटल क्रेडिट कार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- **Paisabazaar**, India's largest financial marketplace, in partnership with **SBM Bank (India) Limited**, has launched the **"SBM Paisabazaar Paisa+ Credit Card"**, a **Fixed Deposit (FD)-backed secured credit card**.
- **भारत के सबसे बड़े वित्तीय मार्केटप्लेस** Paisabazaar ने **SBM Bank (India) Limited** के साथ मिलकर **"SBM Paisabazaar Paisa+ Credit Card"** लॉन्च किया है, जो **Fixed Deposit (FD) आधारित सुरक्षित (Secured) क्रेडिट कार्ड** है।
- The card can be obtained with a **Fixed Deposit starting from ₹2,000**.
- यह कार्ड **₹2,000 से शुरू होने वाली Fixed Deposit (FD)** के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।
- Customers can earn **interest up to 7% per annum (p.a.)** on their Fixed Deposits.
- ग्राहक अपनी **FD पर 7% प्रतिवर्ष (p.a.) तक ब्याज** अर्जित कर सकते हैं।
- The card is designed to help users build their credit history while keeping their deposits secure.
- यह कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपनी **क्रेडिट हिस्ट्री बनाने** में सहायता करता है, जबकि उनकी **FD सुरक्षित** रहती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- **SBM Bank (India) Limited** Established – **2018**
- **SBM Bank (India) Limited** की स्थापना – **2018**
- **SBM Bank (India) Headquarters – Mumbai, Maharashtra**
- **SBM Bank (India) का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र**
- **MD & CEO of SBM Bank (India) Limited – Ashish Vijayakar**

- **SBM Bank (India) Limited के MD एवं CEO – आशीष विजयाकर**
- **A Secured Credit Card** is issued against collateral, such as a **Fixed Deposit (FD)**, making it easier for first-time users to access credit.
- **Secured Credit Card** किसी **संपार्श्विक (Collateral)**, जैसे **Fixed Deposit (FD)**, के आधार पर जारी किया जाता है, जिससे नए उपयोगकर्ताओं के लिए क्रेडिट प्राप्त करना आसान होता है।

Ques: Under the RBI's revised Scale-Based Regulation (SBR) framework, NBFCs with an asset size of ₹1 lakh crore and above will automatically be classified under which layer?

प्रश्न: RBI के संशोधित Scale-Based Regulation (SBR) ढांचे के तहत ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति (Asset Size) वाले NBFCs को स्वतः किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा?

A) Base Layer (NBFC-BL) / बेस लेयर

B) Middle Layer (NBFC-ML) / मिडिल लेयर

C) Upper Layer (NBFC-UL) / अपर लेयर

D) Top Layer (NBFC-TL) / टॉप लेयर

E) Core Investment Layer / कोर इन्वेस्टमेंट लेयर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The **Reserve Bank of India (RBI)** has introduced the revised **Scale-Based Regulation (SBR)** framework for **Non-Banking Financial Companies (NBFCs)** to strengthen **financial stability** and improve **regulatory oversight**.
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** के लिए संशोधित **Scale-Based Regulation (SBR)** ढांचा लागू किया है, जिसका उद्देश्य **वित्तीय स्थिरता** को मजबूत करना और **नियामकीय निगरानी** में सुधार करना है।
- Under the **SBR framework**, NBFCs are regulated based on their **size,**

complexity, interconnectedness and risk profile.

• **SBR ढांचे** के तहत NBFCs को उनके **आकार (Size), जटिलता (Complexity), परस्पर जुड़ाव (Interconnectedness) और जोखिम प्रोफ़ाइल (Risk Profile)** के आधार पर विनियमित किया जाता है।

The framework classifies NBFCs into **four layers**:

- **Base Layer (NBFC-BL)**
- **Middle Layer (NBFC-ML)**
- **Upper Layer (NBFC-UL)**
- **Top Layer (NBFC-TL)**

इस ढांचे में NBFCs को **चार स्तरों** में वर्गीकृत किया गया है:

- **बेस लेयर (NBFC-BL)**
- **मिडिल लेयर (NBFC-ML)**
- **अपर लेयर (NBFC-UL)**
- **टॉप लेयर (NBFC-TL)**

• Under the revised framework, **NBFCs with an asset size of ₹1 lakh crore and above**, based on their latest audited balance sheet, will **automatically be classified as NBFC-Upper Layer (NBFC-UL)** entities.

• संशोधित ढांचे के अनुसार, नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर **₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति** वाले NBFCs को **स्वतः NBFC-Upper Layer (NBFC-UL)** में वर्गीकृत किया जाएगा।

• The amendments **come into force immediately** from the date of issuance.

• ये संशोधन **जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव** से लागू हो गए हैं।

• Earlier, the **₹1 lakh crore threshold** for identifying Upper Layer NBFCs was reviewed **every five years**. Under the revised framework, it will now be **reviewed every three years**.

• पहले **₹1 लाख करोड़** की सीमा की समीक्षा **हर पाँच वर्ष** में होती थी। संशोधित ढांचे के तहत अब इसकी समीक्षा **हर तीन वर्ष** में की जाएगी।

• **All bank-owned NBFCs** will be subject to **Upper Layer norms**, irrespective of their size, except for **stock exchange listing requirements**.

• **सभी बैंक-स्वामित्व वाले NBFCs** उनके आकार की परवाह किए बिना **Upper Layer** के

नियमों के अधीन होंगे, हालांकि **स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग** संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

- RBI has also increased the **large exposure limit** for **Infrastructure Finance Companies (IFCs)** in the **Upper Layer** from **35% to 45% of Tier 1 capital**.
- RBI ने **Upper Layer** की **Infrastructure Finance Companies (IFCs)** के लिए **Large Exposure Limit** को **Tier 1 पूंजी के 35% से बढ़ाकर 45%** कर दिया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- **Scale-Based Regulation (SBR)** for NBFCs was **introduced by RBI in 2021**.
- **NBFCs के लिए Scale-Based Regulation (SBR)** को **RBI ने 2021** में प्रस्तुत किया था।
- **NBFC** stands for **Non-Banking Financial Company**.
- **NBFC** का पूर्ण रूप **Non-Banking Financial Company (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी)** है।
- **Tier 1 Capital** represents a bank or financial institution's **core capital**, which is used to absorb losses and maintain financial stability.
- **Tier 1 पूंजी** बैंक या वित्तीय संस्था की **मुख्य पूंजी** होती है, जिसका उपयोग हानि को वहन करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

Ques: By how much did India's Net External Liabilities decline during the January–March quarter (Q4) of FY 2025–26?

प्रश्न: वित्त वर्ष 2025–26 की जनवरी–मार्च तिमाही (Q4) के दौरान भारत की शुद्ध बाह्य देनदारियाँ (Net External Liabilities) कितनी घटीं?

A) USD 32.4 Billion / 32.4 अरब अमेरिकी डॉलर

B) USD 40.1 Billion / 40.1 अरब अमेरिकी डॉलर

C) USD 45.8 Billion / 45.8 अरब अमेरिकी डॉलर

D) USD 52.4 Billion / 52.4 अरब अमेरिकी डॉलर

E) USD 60.2 Billion / 60.2 अरब अमेरिकी डॉलर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's Net External Liabilities declined by USD 52.4 billion during the January–March quarter (Q4) of FY 2025–26.

• वित्त वर्ष 2025–26 की जनवरी–मार्च तिमाही (Q4) के दौरान भारत की शुद्ध बाह्य देनदारियाँ 52.4 अरब अमेरिकी डॉलर घट गईं।

• At the end of March 2026, India's Net External Liabilities stood at USD 209.9 billion.

• मार्च 2026 के अंत तक भारत की शुद्ध बाह्य देनदारियाँ 209.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहीं।

• The decline reflected both a reduction in foreign-owned assets (foreign liabilities) in India and an increase in overseas financial assets held by Indian residents.

• यह गिरावट भारत में विदेशी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों (विदेशी देनदारियों) में कमी तथा भारतीय निवासियों की विदेशों में रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

• According to RBI data, foreign liabilities decreased by USD 40.1 billion during Q4 FY26.

• RBI के अनुसार FY26 की चौथी तिमाही में विदेशी देनदारियाँ 40.1 अरब अमेरिकी डॉलर घटीं।

• Overseas financial assets of Indian residents increased by USD 12.3 billion during the same period.

• इसी अवधि में भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियाँ 12.3 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ीं।

• Exchange rate movements also contributed to the decline in liabilities when measured in US dollar terms.

• अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापने पर विनिमय दर (Exchange Rate) में बदलाव ने भी देनदारियों में कमी लाने में योगदान दिया।

• The data indicates an improvement in India's external sector position and International Investment Position (IIP).

• यह आँकड़े भारत की बाह्य क्षेत्रीय स्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) में सुधार को दर्शाते हैं।

Static GK (स्थैतिक जीके)

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1935
- RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- RBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Net External Liabilities = External Liabilities − External Financial Assets
- शुद्ध बाह्य देनदारियाँ = बाह्य देनदारियाँ – बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- International Investment Position (IIP) measures a country's external financial assets and liabilities.
- अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) किसी देश की बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मापती है।
- Foreign Liabilities refer to claims of non-residents on domestic entities.
- विदेशी देनदारियाँ घरेलू संस्थाओं पर गैर-निवासियों के दावों को दर्शाती हैं।
- External Financial Assets include overseas investments, deposits, loans and reserve assets held by residents.
- बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियों में विदेशों में किए गए निवेश, जमा, ऋण तथा निवासियों द्वारा धारित रिज़र्व परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।

Ques: In which year was the Goods and Services Tax (GST) implemented in India?
प्रश्न: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस वर्ष लागू किया गया था?

A) 2014 / 2014
B) 2015 / 2015
C) 2016 / 2016
D) 2017 / 2017
E) 2018 / 2018

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Goods and Services Tax (GST) completed 9 years since its implementation on 1 July 2017.

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

• GST introduced the concept of "One Nation, One Tax" by replacing multiple indirect taxes with a unified tax system.

• GST ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को लागू किया।

• More than 1.65 crore taxpayers are currently registered under the GST regime.

• वर्तमान में GST व्यवस्था के अंतर्गत 1.65 करोड़ से अधिक करदाता पंजीकृत हैं।

• GST has significantly improved tax compliance and increased transparency in the taxation system.

• GST ने कर अनुपालन (Tax Compliance) को मजबूत किया तथा कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई है।

• The reform has simplified business operations by creating a common national market.

• इस सुधार ने एक समान राष्ट्रीय बाजार बनाकर व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।

• GST collections have consistently reached record levels, reflecting stronger economic activity and better compliance.

• GST संग्रह लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, जो बेहतर आर्थिक गतिविधियों और अनुपालन को दर्शाता है।

• The tax reform is regarded as a major step towards building a Viksit Bharat.

• यह कर सुधार विकसित भारत (Viksit Bharat) के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

Static GK (स्थैतिक जीके)

• GST Implemented in India – 1 July 2017

• भारत में GST लागू – 1 जुलाई 2017

• Constitutional Amendment for GST – 101st Constitutional Amendment Act, 2016

• GST के लिए संवैधानिक संशोधन – 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016

• GST Council Constituted under – Article 279A of the Constitution

- GST परिषद का गठन – संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है।
- GST Council Chairman – Union Finance Minister
- GST परिषद के अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री
- GST Council Headquarters – New Delhi
- GST परिषद का मुख्यालय – नई दिल्ली
- GST is a Destination-Based Indirect Tax.
- GST एक गंतव्य-आधारित (Destination-Based) अप्रत्यक्ष कर है।

Ques: During Prime Minister Narendra Modi's State Visit to Seychelles, India signed an Umbrella Line of Credit Agreement worth how much to support priority development projects?
प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान प्राथमिक विकास परियोजनाओं के समर्थन हेतु भारत ने कितनी राशि के Umbrella Line of Credit Agreement पर हस्ताक्षर किए?

A) ₹500 crore / ₹500 करोड़

B) ₹750 crore / ₹750 करोड़

C) ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़

D) ₹1,250 crore / ₹1,250 करोड़

E) ₹1,500 crore / ₹1,500 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India and **Seychelles** signed an **Umbrella Line of Credit Agreement** worth **₹1,250 crore**.
- भारत और **सेशेल्स** ने **₹1,250 करोड़** के **Umbrella Line of Credit Agreement** पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement aims to **support priority development projects** in Seychelles.
- इस समझौते का उद्देश्य **सेशेल्स की प्राथमिक विकास परियोजनाओं** को वित्तीय

सहायता प्रदान करना है।

- During the visit, both countries also signed a **Memorandum of Understanding (MoU)** for the implementation of the **Unified Payments Interface (UPI)** in Seychelles.
- यात्रा के दौरान दोनों देशों ने **सेशेल्स में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** लागू करने के लिए **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर भी हस्ताक्षर किए।
- The **UPI** is targeted to become **operational in Seychelles by the end of 2026**.
- **UPI** को **2026 के अंत तक सेशेल्स में परिचालन (Operational)** बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- **Seychelles Capital – Victoria**.
- **सेशेल्स की राजधानी – विक्टोरिया।**
- **Seychelles Currency – Seychellois Rupee (SCR)**.
- **सेशेल्स की मुद्रा – सेशेलोइस रुपया (SCR)।**
- **President of Seychelles – Patrick Herminie**.
- **सेशेल्स के राष्ट्रपति – पैट्रिक हर्मिनी।**
- **Unified Payments Interface (UPI)** was launched by the **National Payments Corporation of India (NPCI)** in **2016**.
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** को **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा **2016** में लॉन्च किया गया था।

Ques: What is the total amount of Senior Unsecured Floating Rate Notes (FRNs) issued by the State Bank of India (SBI) through its London Branch?
प्रश्न: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से कितनी राशि के Senior Unsecured Floating Rate Notes (FRNs) जारी किए हैं?

A) US$100 million / 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर

B) US$200 million / 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर

C) US$300 million / 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर

D) US$500 million / 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर

E) US$1 billion / 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has successfully completed the issuance of US$300 million Senior Unsecured Floating Rate Notes (FRNs).
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के Senior Unsecured Floating Rate Notes (FRNs) सफलतापूर्वक जारी किए हैं।
- The Floating Rate Notes (FRNs) have a maturity period of three years.
- इन Floating Rate Notes (FRNs) की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) तीन वर्ष है।
- The notes have been issued at a coupon rate of SOFR + 100 basis points (bps) per annum, payable quarterly in arrears.
- इन बॉन्ड्स को SOFR + 100 बेसिस पॉइंट (bps) प्रति वर्ष की कूपन दर पर जारी किया गया है, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही (Quarterly in arrears) किया जाएगा।
- The bonds have been issued through SBI's London Branch.
- इन बॉन्ड्स को SBI की लंदन शाखा के माध्यम से जारी किया गया है।
- A Floating Rate Note (FRN) is a bond whose interest rate changes periodically based on a benchmark interest rate.
- Floating Rate Note (FRN) ऐसा बॉन्ड होता है जिसकी ब्याज दर किसी बेंचमार्क ब्याज दर के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है।
- SOFR (Secured Overnight Financing Rate) is the benchmark interest rate in the United States.
- SOFR (Secured Overnight Financing Rate) संयुक्त राज्य अमेरिका की बेंचमार्क ब्याज दर है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- State Bank of India (SBI) Established – 1955.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्थापना – 1955।

- SBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
- SBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
- Chairman of SBI – C. S. Setty.
- SBI के अध्यक्ष – सी. एस. शेट्टी।
- SOFR (Secured Overnight Financing Rate) is administered by the Federal Reserve Bank of New York.
- SOFR (Secured Overnight Financing Rate) का प्रशासन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा किया जाता है।

Ques: Through the partnership between Eurobank and NPCI International Payments Limited (NIPL), UPI has recently gone live in which country?
प्रश्न: Eurobank और NPCI International Payments Limited (NIPL) की साझेदारी के माध्यम से UPI हाल ही में किस देश में शुरू किया गया है?

A) Italy / इटली

B) Greece / ग्रीस

C) Spain / स्पेन

D) Portugal / पुर्तगाल

E) Cyprus / साइप्रस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Unified Payments Interface (UPI) has gone live in Greece, expanding India's global digital payments network.
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ग्रीस में शुरू हो गया है, जिससे भारत का वैश्विक डिजिटल भुगतान नेटवर्क और विस्तारित हुआ है।
- The launch was enabled through a partnership between Eurobank and NPCI International Payments Limited (NIPL).
- यह सेवा Eurobank और NPCI International Payments Limited (NIPL) की

साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई है।

- The announcement was made during Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal's visit to Athens, Greece.
- इसकी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एथेंस (ग्रीस) यात्रा के दौरान की गई।
- With Greece joining the network, UPI is now available in 10 countries in different forms.
- ग्रीस के जुड़ने के साथ UPI अब विभिन्न रूपों में 10 देशों में उपलब्ध हो गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Greece Capital – Athens.
- ग्रीस की राजधानी – एथेंस।
- Greece Currency – Euro (€).
- ग्रीस की मुद्रा – यूरो (€)।
- Eurobank Headquarters – Athens, Greece.
- Eurobank का मुख्यालय – एथेंस, ग्रीस।
- NPCI International Payments Limited (NIPL) is the international arm of the National Payments Corporation of India (NPCI).
- NPCI International Payments Limited (NIPL), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा है।
- Unified Payments Interface (UPI) was launched in 2016 by NPCI.
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को NPCI द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था।

Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), what was India's total external debt at the end of March 2026?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार मार्च 2026 के अंत तक भारत का कुल बाह्य ऋण (External Debt) कितना था?

A) US$ 712.8 billion / 712.8 अरब अमेरिकी डॉलर

B) US$ 726.5 billion / 726.5 अरब अमेरिकी डॉलर

C) US$ 762.8 billion / 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर

D) US$ 782.6 billion / 782.6 अरब अमेरिकी डॉलर

E) US$ 806.4 billion / 806.4 अरब अमेरिकी डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the **Reserve Bank of India (RBI)**, **India's external debt increased by US$26.3 billion** to **US$762.8 billion** at the end of **March 2026** compared to the previous year.

• **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** के अनुसार **मार्च 2026** के अंत तक भारत का **बाह्य ऋण (External Debt) 26.3 अरब अमेरिकी डॉलर** बढ़कर **762.8 अरब अमेरिकी डॉलर** हो गया।

• India's **external debt-to-GDP ratio** increased to **20.8%** from **19.8%** a year earlier.

• भारत का **बाह्य ऋण-से-GDP अनुपात (External Debt-to-GDP Ratio) 19.8%** से बढ़कर **20.8%** हो गया।

• The **US Dollar** remained the dominant currency in India's external debt, accounting for **55.5%** of the outstanding stock.

• भारत के बाह्य ऋण में **अमेरिकी डॉलर** का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसकी हिस्सेदारी **55.5%** थी।

• Debt denominated in the **Indian Rupee** accounted for **29.4%**, followed by the **Japanese Yen (6.4%)**, **Special Drawing Rights (SDR) (4.3%)**, and the **Euro (3.7%)**.

• **भारतीय रुपये** में नामित ऋण की हिस्सेदारी **29.4%** रही, इसके बाद **जापानी येन (6.4%)**, **स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) (4.3%)** तथा **यूरो (3.7%)** का स्थान रहा।

• The **valuation impact** during the year amounted to **US$24.6 billion**. Excluding this effect, external debt would have increased by **US$51 billion**.

• वर्ष के दौरान **मूल्यांकन प्रभाव (Valuation Impact) 24.6 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा। इस प्रभाव को हटाने पर बाह्य ऋण में **51 अरब अमेरिकी डॉलर** की वृद्धि होती।

• **Long-term external debt** (original maturity of more than one year) stood at **US$613.5 billion**, while **short-term debt** accounted for **19.6%** of the total external debt.

• **दीर्घकालिक बाह्य ऋण** (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता) **613.5 अरब अमेरिकी**

डॉलर रहा, जबकि **अल्पकालिक बाह्य ऋण** कुल बाह्य ऋण का **19.6%** था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- **Reserve Bank of India (RBI)** Established – **1 April 1935**.
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** की स्थापना – **1 अप्रैल 1935**।
- **RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra**.
- **RBI** का मुख्यालय – **मुंबई, महाराष्ट्र**।
- **RBI Governor – Sanjay Malhotra**.
- **RBI के गवर्नर – संजय मल्होत्रा**।
- **Special Drawing Rights (SDR)** is an international reserve asset created by the **International Monetary Fund (IMF)**.
- **स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा निर्मित एक **अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति (International Reserve Asset)** है।

Ques: Kakinada Cooperative Town Bank of Andhra Pradesh secured which Tier status under the RBI norms after its total deposits crossed ₹2,000 crore?
प्रश्न: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक ने कुल जमा राशि ₹2,000 करोड़ से अधिक होने के बाद RBI के मानदंडों के अनुसार कौन-सा टियर (Tier) दर्जा प्राप्त किया?

A) Tier-I / टियर-I

B) Tier-II / टियर-II

C) Tier-III / टियर-III

D) Tier-IV / टियर-IV

E) Tier-V / टियर-V

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Andhra Pradesh's Kakinada Cooperative Town Bank, an Urban Cooperative Bank (UCB), secured Tier-III status under the Reserve Bank of India (RBI) norms.
- आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, जो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCB) है, ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मानदंडों के अनुसार Tier-III का दर्जा प्राप्त किया।
- The bank achieved this milestone after its total deposits surpassed ₹2,000 crore, while maintaining zero Net Non-Performing Assets (NPAs).
- बैंक ने ₹2,000 करोड़ से अधिक कुल जमा राशि तथा शून्य नेट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Net NPAs) के साथ यह उपलब्धि हासिल की।
- Following this achievement, the bank became the second-largest among the 46 Urban Cooperative Banks (UCBs) in Andhra Pradesh, with its total business exceeding ₹2,040 crore.
- इस उपलब्धि के बाद बैंक आंध्र प्रदेश के 46 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, जिसका कुल व्यवसाय ₹2,040 करोड़ से अधिक हो गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Classification of Urban Cooperative Banks (UCBs) under RBI:
- RBI के अनुसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) का वर्गीकरण:
- Tier-I – Deposits below ₹100 crore.
- Tier-I – ₹100 करोड़ से कम जमा।
- Tier-II – Deposits up to ₹1,000 crore.
- Tier-II – ₹1,000 करोड़ तक जमा।
- Tier-III – Deposits between ₹1,000 crore and ₹10,000 crore.
- Tier-III – ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच जमा।
- Tier-IV – Deposits above ₹10,000 crore.
- Tier-IV – ₹10,000 करोड़ से अधिक जमा।